साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 27 | प्रति सोमवार इंदौर, 05 फरवरी से 11 फरवरी 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

अंतरिम बजट 2024

मित्रों का पोषण जनता का शोषण

जनधन से रेलवे सड़कों का निर्माण, जनता से लूट के अड्डे

डकैत सत्ताधीशों को जनता की बेरोजगारी भुखमरी अशिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग व्यवसाय से कोई मतलब नहीं? आदर्श संरचना विकास में 50 से 70% तक कमीशन पर सड़कें रेल लाइन...

भारत का 2024 का अंतिम बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत कर दिया गया जो स्पष्ट करता है की भाजपा को देश, देश की जनता का शोषण कर केवल अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सड़क रेलवे लाइन आदि की अधो संरचना का विकास के नाम 50 से 80% तक कमीशन हजम करनाऔरनिर्माण के बादफिर उनको घाटे में दिखाकर अपने मित्रों को अंतरित करने का 10 साल में षड्यंत्र करने के अतिरिक्त उसका ध्यान 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की बेरोजगारी भुखभरी को दूर करने नए रोजगार सृजित करने उद्योग व्यवसाय धंधो के प्रोत्साहन के लिए कोई सोच व्यवस्था तक नहीं है। वैसे भी बजट झूठे समंकों की बाजीगरी ज्यादा होता है। फिर भी बजट की प्रस्तुति सरकार में बैठे सत्ताधीशों की मंशा और उसके भविष्य को निर्धारित व परिभाषित करती है। बेशक प्रस्तुत बजट में प्रदेश और विशेष रूप से मालवा को रेलवे लाइनों के लिए बजट का आवंटन भरपूर दिया है परंतु रेलवे के रतलाम मंडल के मक्कार इंजीनियर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर काम को कछुए की धीमी गति से कर जानबूझकर समय विस्तार महंगाई मैं मोटा धन हड़पते रहे व चाहते हैं। इसलिए उस आवंटित धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोलियम पर 80% कर के बाद में भी रुपए 15000 करोड़ देकर अपने खास मित्रों अंबानी की रिफाइनरी को जो अपना तेल रिफाइन कर के सरकारी तेल कंपनियों को बेंचती है। धन लुटाया जा रहा है। जबकि तेल कंपनी में पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटी हुई तेल की कीमतों रूस से 60% तक आयात कर रही है और पिछले साल भर में 2 लाख करोड रुपए का मुनाफा कमा चुकी है।

(विस्तृत पढ़ें पेज 7 पर)

अमेरिकी विमानों का सीरिया, इराक, जार्डन आतंकियों के ठिकानों पर हमला

होतियों के जहाजों पर हमले के प्रतिकार में अमेरिकन हमले

क्या एशिया में आक्रमण कर रूस चीन को चमका युक्रेन को अपनी उपस्थिती से समर्थन

घातक ड्रोन हमले का बदला लेते हुए अमेरिका ने इराक और सीरिया में आतंकियों पर प्रहार

घातक ड्रोन हमले का बदला लेते हुए अमेरिका ने इराक और सीरिया में मिलिशिया पर कड़ा प्रहार किया ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी हमले सीधे तौर पर ईरान या उसकी सीमाओं के भीतर रिवोल्यूशनरी गार्ड कुद्स फोर्स के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि अमेरिका संघर्ष को और भी अधिक बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जॉर्डन हमले के पीछे अपना हाथ होने से इनकार किया है। प्लैनेट लैब्स पीबीसी की एक सैटेलाइट तस्वीर सोमवार, 29 जनवरी को पूर्वोत्तर जॉर्डन में टॉवर 22 के नाम से जाना जाने वाला एक सैन्य अड्डा दिखाती है। अमेरिकी सेना ने इराक और सीरिया में ईरानी समर्थित मिलिशिया और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों स्थलों पर हवाई हमला किया,

(शेष पेज 2 पर)

अमेरिकी व ईसाई मिशनरियों का दुनिया को हांकने का षडयंत्र

न्यू वर्ल्ड आर्डर

न्यू वर्ल्ड आर्डर के कुछ चरण पूर्व निर्धारित हैं और यह सब एक साथ पूरी दुनियां में हो रहा है।

कुछ देश पहले चरण में हैं। तो कुछ देश अंतिम चरण में। लेकिन इस न्यू वर्ल्ड आर्डर के निर्देशों का पालन हर देश को करना ही पड़ेगा।

किन्तु अभी भी विश्व के मात्र 4 देश हैं। जो न्यू वर्ल्ड आर्डर को नहीं मान रहे हैं। जिसमें से एक देश चीन भी है।

न्यू वर्ल्ड आर्डर के तहत चरण बध्य योजना :-

प्रथम चरण :- जनधन योजना के तहत हर व्यक्ति का एक बैंक खाता होना अनिवार्य है।

नोट बन्दी द्वारा घर में पड़े नोट को बैंक में जमा करवाना।

प्रत्येक नागरिक का एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष पहचान पत्र आधार कार्ड जारी करना या उसका निर्माण करवाना। आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ना।

दूसरा चरण :- फिर कैश लैस सोसायटी निर्माण की प्रक्रिया का आरम्भ। जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे आदि पद्यति अपनायी जायेगी।

फिर सभी भुगतान R.F.I.D. चिप द्वारा किया जायेगा। फिर विश्व की एक मुद्रा की स्थापना होगी।

तीसरा चरण :- फिर आबादी घटाने के लिये नये-नये विषाणु छोड़े जायेंगे।

विश्व की कुल आबादी मात्र 50 करोड़ होगी।

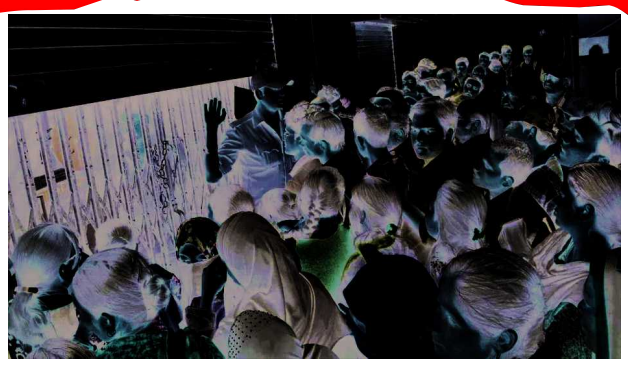

नयी आबादी विकसित न हो इसलिये वैक्सीनेशन द्वारा अगली पीढ़ी रोक दी जायेगी।

चौथा चरण :- फिर बचे हुये लोगों के मस्तिष्क में एक चिप इंप्लांट किया जायेगा।

जिसके द्वारा आपको निर्देश दिये जायेंगे। निर्देश न मानने पर रेडियेशन द्वारा आपका मस्तिष्क हेंग आउट कर दिया जायेगा या उसी चिप में छुपे जहर द्वारा आपको मार दिया जायेगा।

इस तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आपकी हर गतिविधि नैनो चिप के द्वारा विश्व सत्ता द्वारा नियंत्रित होगी।

आपका आहार-विहार-विचार सब कुछ उनके नियंत्रण में होगा।

आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका ज्ञान, आपकी संतान सब कुछ विश्व सत्ता के नियंत्रण में होगा।

समाज में कृत्रिम भुखमरी, कृत्रिम अज्ञानता, कृत्रिम आभाव, कृत्रिम निर्धनता, कृत्रिम मुद्रा और सम्पत्ति का अवमूलन, निष्क्रिय न्याय व्यवस्था, कृत्रिम प्रशासनिक निष्क्रियता, जगह-जगह धर्म-जाति-क्षेत्र-भाषा के आधार पर कृतिम गृह युद्ध, कृतिम अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र, खाद्यानों पर टैक्स आदि।

विश्व सत्ता की इच्छा के बिना आप किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं ले सकेंगे।

(शेष पेज 3 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

सत्ताधीशों को राष्ट्र हित नहीं स्वहितों की व्यवस्था से मतलब

अशिक्षित आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति को छल बल, दल से सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाए या मिल जाए तो जनता को क्या परिणाम भुगतने पढ़ सकते हैं? वर्तमान के सत्ता धीशों की कार्यशैली से स्पष्ट होता है। वैसे ही जैसे एक लोहार, तेली, बढ़ई को किसी सर्व सुविधा युक्त फल फूल के वृक्षों के फलते फूलते बगीचे की देखरेख सौंप दी जाए तो वह बगीचे का क्या हाल करेगा? समझा जा सकता है। वहीं हाल भारत की सत्ता और उसके अर्थव्यवस्था का हो रहा है। लोहार उसके चारों तरफ के घेराबंदी किए हुए लोहे के तारों, दरवाजों, बिजली के खंबो, सिंचाई की मोटरों, फव्वारों को निकाल कर लोहे का उपयोग अपने हित में करेगा। वही हाल तेली बिना समय लगाये फल फूलों से तेल निकालने की अपेक्षा संसाधनों को निचोड़ कर वसूलेगा। बढ़ई को उसके फल फूलों की फसल की आय से नहीं वहां लगे पेड़ों की लकड़ी से मतलब होगा। की कब उसे मौका मिले और वह पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ी को अपने हिसाब से चीर फाड़ कर टेबल कुर्सी पलना व अन्य बिक्री योग्य सामग्री बनाकर बेचकर पैसा हजम करें। वही हाल वर्तमान की सत्ता केंद्र से लेकर राज्यों तक में कर रही है। देश के प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों राजस्व आय का उपयोग राष्ट्र की जनता के हित में नहीं वरन अधोसंरचना विकास व निर्माण के नाम परअपने 50 से 70% तक कमीशन खाने, 5से 10 गुना ज्यादा की डीपीआर बना 80% तक शासकीय बैंकों मैं जमा जनधन को हड़पने, धन उधार लेने का षड्यंत्र कर एक तरफ बैंकों को कंगाल करने पर तुले हैं तो दूसरी तरफ भारी भरकम 1500 से ज्यादा वस्तुओं व सेवाओं पर ठोके गए जनधन का पैसा वहां खर्च दिखाकर बीच में हड़प भी रहे हैं। जब पूरी संपत्तियों रेलवे लाइन सड़कों विद्युत संचार कंपनियों में लाभ आने लगे तो वहां भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को बैठा रखरखाव खरीदी को कई गुना ज्यादा लागत दिखा मोटा पैसा हजम कर घाटे में दिखा अपने पूंजीपति मित्रों को अंतरित करने का षड़यंत्र करते हैं। जैसा की सड़कों रेलवे लाइनऑन विद्युत कंपनियां संस्थानों में पिछली 10 वर्षों से काफी ऊंचे स्तर पर खेला जा रहा है। आखिर कब तक पोर्शन और जनता का शोषण किया जाता रहेगा? हाल के बजट में ही 11% बजट केवल सड़कों और रेलवे लाइन को बनाने बिछाने के लिए आवंटित किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था का वर्तमान आधार भी कृषि ही है। जो जनता की आधारभूत आवश्यकता भूख को पोषित करने के साथ देश की सकल आय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ उद्योग धंधों के कच्चे माल की निर्भरता को मजबूत करने के लिएकृषि के विकास पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जहां किसानों को खाद बीज पर अनुदान देने के साथ अनाज दलहन तिलहन की अधिकतम पैदावार के लिए अधिकतम अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हमारी विदेशों पर निर्भरता खत्म हो सके। की अपेक्षा अधोसंरचना के विकास के नाम पर अधिकतम कृषि भूमि को देश भर में बर्बाद किया जा रहा है। आखिर कब तक अपने मित्रों के पोषण के लिए जनधन को बर्बाद करने के साथ हर वर्ष पूरे देश में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि की बलि चढ़ाई जाती रहेगी। आखिर भूख मनुष्य के जीवन की पहली आवश्यकता है।

होतियों के जहाजों पर हमले के प्रतिकार में अमेरिकन हमले

पेज 1 का शेष

जो पिछले सप्ताहांत जॉर्डन में ड्रोन हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाबी कार्रवाई में था। बड़े पैमाने पर हुए हमलों ने सात स्थानों पर 85 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिनमें कमांड और नियंत्रण मुख्यालय, खुफिया केंद्र, रॉकेट और मिसाइल, ड्रोन और गोला-बारूद भंडारण स्थल और अन्य सुविधाएं शामिल थीं जो मिलिशिया या आईआरजीसी के कुद्स फोर्स, गार्ड के अभियान दल से जुड़ी थीं। वह इकाई जो क्षेत्रीय मिलिशिया के साथ तेहरान के संबंधों और उन्हें हथियारों से लैस करने का काम संभालती है। और राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक बयान में स्पष्ट किया कि अभी और भी बहुत कुछ आएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी हमले सीधे तौर पर ईरान या उसकी सीमाओं के भीतर रिवोल्यूशनरी गार्ड कुद्स फोर्स के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि अमेरिका संघर्ष को और भी अधिक बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जॉर्डन हमले के पीछे अपना हाथ होने से इनकार किया है। यह स्पष्ट नहीं था कि हड़तालों का क्या असर होगा। कई दिनों की अमेरिकी चेतावनियों ने मिलिशिया सदस्यों को छिपने के लिए तितर-बितर कर दिया होगा। कई देशों में विभिन्न स्थानों पर कई समूहों के सक्रिय होने के कारण, किसी बड़े झटके की संभावना नहीं है। हालांकि मुख्य ईरान समर्थित मिलिशिया में से एक, कातिब हिजबुल्लाह ने कहा कि वह अमेरिकी सैनिकों पर हमले रोक रहा है, अन्य ने लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है, खुद को फिलिस्तीनी कारण के चैंपियन के रूप में पेश किया है जबकि गाजा में युद्ध समाप्त होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। 'हमारी प्रतिक्रिया आज से शुरू हुई। यह हमारी पसंद के समय और स्थानों पर जारी रहेगा,' बिडेन ने चेतावनी देते हुए कहा, 'उन सभी को जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यह जान लें: यदि आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम जवाब देंगे।' वह और अन्य शीर्ष अमेरिकी नेता कई दिनों से कह रहे थे कि कोई भी अमेरिकी प्रतिक्रिया केवल एक हिट नहीं होगी बल्कि समय के साथ 'स्तरीय प्रतिक्रिया' होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि नागरिक हताहतों से बचने के लिए लक्ष्यों को सावधानीपूर्वक चुना गया था और यह स्पष्ट, अकाट्य सबूतों पर आधारित था कि वे क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों पर हमलों से जुड़े थे। उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह सबूत क्या था। विज्ञापन ज्वाइंट स्टाफ के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डगलस सिम्स ने कहा, हमले लगभग 30 मिनट तक हुए और जिन स्थानों पर हमला किया गया उनमें से तीन इराक में और चार सीरिया में थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले में 125 से अधिक सटीक युद्ध सामग्री शामिल थी, और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से उड़ाए गए लंबी दूरी के बी-1 बमवर्षक सहित कई विमानों द्वारा वितरित किया गया था। सिम्स ने कहा कि मौसम एक कारक था क्योंकि अमेरिका ने हमले की योजना बनाई थी ताकि अमेरिका को यह पुष्टि करने की अनुमति मिल सके कि वह सही लक्ष्यों पर हमला कर रहा है और नागरिक हताहतों से बच रहा है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मिलिशिया सदस्य मारे गए थे। सिम्स ने कहा, 'हम जानते हैं कि ऐसे आतंकवादी हैं जो इन स्थानों का उपयोग करते हैं, आईआरजीसी के साथ-साथ ईरानी-गठबंधन मिलिशिया समूह के कर्मी भी हैं।' 'हमने आज रात ये हमले इस विचार के साथ किए कि उन सुविधाओं के अंदर लोगों के साथ हताहत होने की संभावना होगी।' सीरियाई राज्य मीडिया ने बताया कि हताहत हुए हैं लेकिन संख्या नहीं बताई। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि सीरिया हमलों में 18 आतंकवादी मारे गए। इराकी सेना के प्रवक्ता याह्या रसूल ने एक बयान में कहा कि अल-क़ैम शहर और सीरिया के साथ देश की सीमा से लगे इलाके अमेरिकी हवाई हमलों से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, 'ये हमले इराकी संप्रभुता का उल्लंघन हैं और इराकी सरकार के प्रयासों को कमजोर करते हैं, जिससे एक खतरा पैदा होता है जो इराक और क्षेत्र को अवांछनीय परिणामों की ओर ले जाएगा।' किर्बी ने कहा कि अमेरिका ने हमले करने से पहले इराकी सरकार को सतर्क कर दिया था। यह हमला बिडेन और शीर्ष रक्षा नेताओं के शोक संतप्त परिवारों में इस्राइली या अमेरिकी हितों पर हमले को उचित ठहराने के लिए संघर्ष का इस्तेमाल किया है, जिसमें लगभग दैनिक आदान-प्रदान में लाल सागर क्षेत्र में नागरिक वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को ड्रोन या मिसाइलों से धमकी देना शामिल है।

गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, 'यह मध्य पूर्व में एक खतरनाक क्षण है।' उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा, और चेतावनी दी, 'इस समय, हमने अतीत में जितनी क्षमताएं ली हैं, उससे भी अधिक क्षमता छीनने का समय आ गया है।'

एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के अनुसार, मंगलवार तक, ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों

शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद हुआ, जब डेलावेयर में डोवर एयर फोर्स बेस पर तीन आर्मी रिजर्व सैनिकों के अवशेष अमेरिका को लौटाए गए थे।

शुक्रवार सुबह ही, ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने अपने हितों को निशाना बनाने वाले किसी भी अमेरिकी हमले के लिए संभावित रूप से जवाबी कार्रवाई करने के तेहरान के पहले के वादों को दोहराया। रायसी ने कहा, ''हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश, कोई क्रूर ताकत हमें धमकाना चाहती है, तो इस्लामी गणतंत्र ईरान कड़ी प्रतिक्रिया देगा।''

इस सप्ताह एक बयान में, कताइब हिजबुल्लाह ने 'इराकी सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कब्जे वाले बलों के खिलाफ सैन्य और सुरक्षा अभियानों को निलंबित करने की घोषणा की।' लेकिन उस दावे का स्पष्ट रूप से अमेरिकी हमले की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईरान समर्थित अन्य प्रमुख समूहों में से एक, हरकत अल-नुजाबा ने शुक्रवार को अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने की कसम खाई।

अमेरिका ने जॉर्डन में हमले के लिए इराक में इस्लामी प्रतिरोध, ईरान समर्थित मिलिशिया के एक व्यापक गठबंधन को दोषी ठहराया है, लेकिन इसे किसी विशिष्ट समूह तक सीमित नहीं किया है। हालाँकि, कताइब हिजबुल्लाह एक शीर्ष संदिग्ध है।

कुछ मिलिशिया वर्षों से अमेरिकी ठिकानों के लिए खतरा रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमले के बाद हमास के साथ इज़राइल के युद्ध के मद्देनजर समूहों ने अपने हमले तेज कर दिए, जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया। युद्ध के कारण गाजा पट्टी में 27,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और मध्य पूर्व में आग भड़क उठी।

पूरे क्षेत्र में ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों ने 18 अक्टूबर से अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर 166 हमले किए थे, जिनमें इराक में 67, सीरिया में 98 और अब जॉर्डन में एक हमला शामिल है। आखिरी हमला 29 जनवरी को इराक में अल-असद एयरबेस पर हुआ था और इसमें कोई घायल या क्षति नहीं हुई थी।

इस बीच, एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, अमेरिका ने जॉर्डन के टॉवर 22 बेस पर सुरक्षा बढ़ा दी है, जिस पर रविवार को ईरान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था। अधिकारी ने कहा, जबकि इराक और सीरिया में पिछली अमेरिकी प्रतिक्रियाएँ अधिक सीमित थीं, जॉर्डन में तीन सेवा सदस्यों की मौतें एक सीमा पार कर गईं।

वह हमला, जिसमें 40 से अधिक सेवा सदस्य भी घायल हुए थे - मुख्य रूप से आर्मी नेशनल गार्ड - इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ईरान समर्थित मिलिशिया से अमेरिकी युद्ध में मौत का पहला परिणाम था। टॉवर 22 में लगभग 350 अमेरिकी सैनिक हैं और यह जॉर्डन और सीरिया के बीच सीमा पर असैन्यीकृत क्षेत्र के पास स्थित है। इराकी सीमा केवल 6 मील (10 किलोमीटर) दूर है।

इसके अलावा शुक्रवार को, इजरायली सेना ने कहा कि उसकी तीर रक्षा प्रणाली ने लाल सागर से देश की ओर आने वाली एक मिसाइल को रोक दिया, जिससे संदेह पैदा हुआ कि इसे यमन के हौथी विद्रोहियों द्वारा लॉन्च किया गया था। विद्रोहियों ने तुरंत जिम्मेदारी का दावा नहीं किया।

और एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि सेना ने शुक्रवार को यमन के अंदर आसन्न खतरा समझे जाने वाले हौथी सैन्य ठिकानों के खिलाफ अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले किए हैं। हौथी द्वारा संचालित उपग्रह समाचार चैनल अल-मसीरा ने कहा कि ब्रिटिश और अमेरिकी सेना ने उत्तरी यमनी प्रांत हज्जाह, जो हौथी का गढ़ है, में तीन हमले किए।

कलेक्टर : कलेक्ट कर ऊपर भेज

शासकीय भू कालोनी माफिया का संरक्षक कलेक्टर

प्रदेश में नया मुख्यमंत्री मोहन यादव का इतिहास और वर्तमान स्वंय ही भू कॉलोनी शराब ईंट-भट्टा माफिया आदि का है। अब तो प्रदेश की सत्ताही उसके हाथ में है फिर इंदौर के भू कॉलोनी माफिया के रूप में जाने, जाने वाले इंदौर के पूर्व के महापौर कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश का शहरीय विकास मंत्री बना दिया है। तो स्वाभाविक है की अब जनता के जीवन-यापन व रोजगार विकास कार्यों से ज्यादा सबका सारा ध्यान बची हुई सरकारी जमीनों कार्यालयों को या इनके प्रकरणों से संबंधित खेलों पर केंद्रित रहेगा जैसा कि आते ही साथ वर्तमान के इंदौर सांसद शंकर लालवानी का बंगला जो कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के लिए आरक्षित था पर घर जालसाज पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह के माध्यम से उस पर कब्जा जमाया और अब उसकी लार उसे बंगले को हड़प जाने के साथ एकमात्र पूर्वी क्षेत्र में पलासिया में जो थोड़ी खुली जमीन जहां पर अच्छा खासा बगीचा लगा है और वह ऐतिहासिक मुख्य अभियंता कार्यालय जोकि 1836 का बना हुआ है।

जो कि यथार्थ में अब हेरिटेज बिल्डिंग बन चुका है। व उसके चारों तरफ के सरकारी बंगले क्वार्टर्स आदि पर छल कपट के माध्यम से जिस जमीन की कीमत अब अरबों रुपए में हो गई है हाउसिंग बोर्ड को सौंप और उनके कार्यालय वह आवास के लिए रेनू रेजिडेंसी जो बहुत महंगी होने के कारण बिक नहीं रही है को जमीन के बदले में देकर वर्तमान पलासिया की लोनिवि की की जमीन को विकसित करने के नाम परबहु मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर उसे पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को नष्ट कर भूमि को कंकरीट जंगल में बादल रुपए की कमाई शंकर लालवानी, कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव के साथ घोर धूर्त गृह निर्माण मंडल के इंजीनियर से लेकर मंत्री तक करना चाहते हैं।

इसलिए उस एकमात्र सुंदर बगीचे और ऐतिहासिक महत्व के भवन को नष्ट करना चाहते हैं वैसे भी उसे मुख्य अभियंता कार्यालय के पास देश के आजाद होने के बाद इंदौर राज्य की भूमि भवन बाजारों का जो कार्य था दूसरी तरफ यह मुख्य अभियंता कार्यालय का 400 हेक्टेयर का क्षेत्रफल था जो पश्चिम में वर्तमान के पलासिया थाने से लेकर दक्षिण में वर्तमान के नारी

सब नेताओं अधिकारियों पूंजीपतियों की निगाहें जमीनों के खेल पर...

निकेतन से पूर्व में कनाडिया रोड तक उत्तर में पेट्रोल पंप तक फैला हुआ था जिसमें बाद में हेरा फेरी चालबाजी, जालसाजी से जमीनों पर कब्जा कर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई और बचे हुए हिस्से पर भी शासकीय वा अशासकीय भू कॉलोनी माफिया गिद्धों की निगाहें टिकी हुई है।

जहां तक गृह निर्माण मंडल के घोर भ्रष्ट जालसाज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर प्रधान सचिव, आयुक्त, उपायुक्तों से लेकर उसके सभी कार्यालयों मैं बैठे कार्यपालन सहायक उप यंत्रियों इंजीनियर का सवाल है, तो इसका बढ़िया उदाहरण है इंदौर की सांवेर रोड पर बनने वाली जेल है जो पिछले 20 सालों से विभिन्न तरीकों से विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिनमें लोक निर्माण विभाग की की भवन शाखा को भी हजार करोड रु से ज्यादा खर्च हो जाने के बाद में भी वह जेल अभी तक पूरी नहीं हुई है।

100 करोड़ की लागत से बनने वाली वह जेल समय विस्तार महंगाई अधूरे कार्य और उपयोग न करने से हुई टूट फूट के कारण उसकी कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है तो अंदाज लगाया जा सकता है इससे हमें रोड की वजह जो 2 साल में पूरी हो जानी चाहिए थी 20 साल बीच जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी और वह जेल लोड की जेल तोड़कर वहां पर भी बहुमत जिला इमारत बनाने का अध्ययन निर्माण मंडल का सपना अभी भी सपना ही बनी है।

दूसरी तरफ इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी होने के कारण यहां पर पूंजीपति भू कॉलोनी माफिया जो स्वयं अब प्रदेश के मंत्री भी हैं राजस्व अधिकारी के रूप में उस जिलाधीश की पदस्थी करवाते हैं। जो उनके इसारे पर नाच उनके हितों को साध सके और वर्तमान में पदस्थ कलेक्टर आशीष सिंह को भी उनकी मर्जी से ही ग्रेटर रिंग रोड में जमीनों कीऔर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिग्रहण से पहले ही ओने पौने में खरीद कर उसे 139 किमी लंबे ग्रेटर रिंग रोड पर अपना व्यवसायिक उपयोग कर मोटी कमाई कर सकें। फिर हर जिलों का कलेक्टर सरकारी बड़ा अधिकार युक्त भू कॉलोनी माफियाओं का संरक्षण दाता व संरक्षक होता है। राजस्व में बैठे पटवारी और राजस्व निरीक्षक नायब व तहसीलदार सहायक, उपजिलाधीश, जिलाधीश, आयुक्त तक सब जमीनों के बड़े खिलाड़ी जादूगर जालसाज होते हैं जो करोड़ों रू हजम कर इस खेल में भू और कॉलोनी माफिया को संरक्षण देते रहते हैं। इसलिए आते ही साथ कलेक्टर आशीष सिंह ने भीग्रेटर रिंग रोड के दोनों तरफ की कृषकों वह ग्रामीणों की भूमि की खरीद बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया।

मामला ग्रेटर रिंग रोड का, पंजीयन विभाग ने जारी किए आदेश

किसानों का भी विरोध जारी, महापंचायत भी आयोजित

ग्रेटर रिंग रोड निर्माण के लिए 34 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण एनएचआई द्वारा कराया जा रहा है, जिसके चलते पहले सभी जमीनों की रजिस्ट्रियों पर रोक प्रशासन ने लगा दी, जिस पर हल्ला मचा और अग्रिबाण ने भी खबर का प्रकाशन किया। उसके बाद पंजीयन विभाग ने कल रात एक नया आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि जो जमीनें रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाना है उन्हीं की रजिस्ट्रियों पर रोक रहेगी, शेष पर नहीं। यानी अब लगभग 1100 एकड़ जमीनों को छोडक़र शेष जमीनें मुक्त कर दी और इनकी रजिस्ट्रियां भी पूर्व की तरह जारी रहेगी। दूसरी तरफ इस रोड के लिए भी किसानों का विरोध जारी है। लगातार बैठकें और महापंचायत आयोजित की जा रही है। किसान बाजार दर से चार गुना अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आउटर रिंग रोड और पश्चिमी के साथ इंदौर-बुधनी रेल लाइन के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके चलते इससे संबंधित किसान व अन्य संगठन लामबंद हो गए। पूर्व जनपद सदस्य और किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बताया कि कल भी धार जिले के खंडवा ग्राम में किसानों की महापंचायत आयोजित हुई और आज भी बैठकों और विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला जारी है।

ग्रेटर रिंग रोड के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों का भी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और बदले में अत्यंत कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिसे चार गुना तक बाजार दर से दिए जाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रेटर रिंग रोड के लिए कार्यालय कलेक्टर के 24.11.2023 के पत्र के माध्यम से 34 गांवों की जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक ल गाई गई थी, जिसे कल हटा लिया है। अब सिर्फ धारा 3 (ए) में प्रकाशित सर्वे नम्बरों की जमीनों को छोडक़र शेष अप्रभावित भूमियों के क्रय-विक्रय पर कोई रोक नहीं है। यानी उनकी रजिस्ट्रियां होती रहेंगी। पिछले दिनों नेशनल हाईवे ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए सांवेर, हातोद, देपालपुर के उन गांवों की जमीनों के खसरे नम्बरों को भी प्रकाशित किया था जिन्हें रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना है। लिहाजा उन खसरों की जमीनों पर ही अब यह रोक रहेगी और शेष जमीनें रोक के दायरे से बाहर रहेगी। दूसरी तरफ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी आज आंदोलनरत किसानों से मिलने पहुंचे। जमीन पर बैठकर किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और उनके साथ अन्याय ना होने देने का आश्वासन भी दिया।

इधर सालों से उद्योग लगाने के लिए नहीं मिल पा रही जमीन

शहर में उद्योग लगाने के लिए जिला उद्योग व्यापार केंद्र के पास सालों से 1 इंच भी जमीन नहीं है। दूसरी तरफ लगभग 12 साल से बंद पड़े 8 उद्योगों के पास 22 लाख वर्गफीट से ज्यादा जमीन उनके कब्जे में फंसी हुई है। प्रशासन को अपनी ही जमीन वापस लेने में पसीने छूट रहे हैं। जिला उद्योग व्यापार केंद्र इंदौर के मुताबिक ये 8 उद्योग कई सालों से बंद पड़े हैं, इसलिए नियम अनुसार इन सभी उद्योगों को बेदखली का नोटिस देकर इनसे जमीन वापस लेने की कार्रवाई शुरू की गई है। विभागीय कार्रवाई के विरोध में इन सबने कोर्ट में अपना दावा ठोंक दिया। इसके बाद से इन औद्योगिक जमीनों के मामले साल 2011 से उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में लंबित हैं।

करोड़ों रुपए कीमत हो चुकी है जमीनों की

यह बंद पड़े उद्योग सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर-बी, सेक्टर-सी और सेक्टर-डी के अलावा पोलोग्रांउड औद्योगिक क्षेत्र में हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से उद्योगों के लिए यह प्राइम लोकेशन है। आज के समय में बंद पड़े कई उद्योगों के कब्जे वाली जमीन की कीमत करोड़ों रुपए है।

इन उद्योगों के पास फंसी पड़ी है जमीन

हिंदुस्तान यूनिलीवर की 239928 वर्गफीट, इंडियन सोया की 1620160 वर्गफीट, मेटलमैन इंडिया की 14000 वर्गफीट, एमपीडीटीएम ग्लोबल की 166841 वर्गफीट, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज की 48400 वर्गफीट, मेटलमैन पाइप मैन्यूफैक्चरिंग की 130680 वर्गफीट, केनस्टार की 4640 वर्गफीट, जेएम इंटरप्राइजेस की 9000 वर्गफीट जमीन, इस तरह कुल मिलाकर 22 लाख 33 हजार 649 वर्गफीट जमीन इन 8 उद्योगों के कब्जे में फंसी पड़ी है। इनसे जमीन वापस लेने के लिए जिला उद्योग व्यापार केंद्र कई सालों से कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहा है।

बंद पड़े उद्योगों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए हमने 9 विशेषज्ञ वकीलों को जिम्मेदारी दी है। हमारे वकीलों की पैनल का कहना है कि न्यायालय के माध्यम से इस साल में हम इन उद्योगों के कब्जे से जमीन वापस ले लेंगे।

-एसएस मंडलोई,
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग व्यापार केंद्र

अमेरिकी व ईसाई मिशनरियों का दुनिया को हांकने का षडयंत्र

पेज 1 का शेष

यहां तक कि आप क्या खायेंगे, किस रंग का कपड़ा पहनेंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किस से क्या बात करेंगे, यह सारी बातें उस विश्व सत्ता के नियंत्रण में होंगी।

जो व्यक्ति इसका विरोध करेगा। पहले तो उसके मस्तिष्क को हैंग आउट कर दिया जायेगा फिर दुबारा गलती करने पर उसकी हत्या कर दी जायेगा।

क्योंकि विश्व सत्ता को पूरी दुनिया चलाने के लिये मात्र 50 करोड़ लोगों की आवश्यकता है।

जबकि आज विश्व की आबादी 800 करोड़ से अधिक है। ऐसी स्थिति में 750 करोड़ लोगों को इस धरती से विदा लेना होगा।

विश्व सत्ता को मात्र वही विश्वसनीय आज्ञाकारी लोगों की आवश्यकता है जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करें। शेष सभी लोगों को यह धरती छोड़ कर जाना होगा।

इसके लिये समय-समय पर पूरी दुनिया में घातक विषाणु छोड़े जायेंगे। जिन से बचने की दवा विश्व सत्ता के नियंत्रण में होगी।

जो व्यक्ति विश्व सत्ता के अनुरूप नहीं होगा। उसे वह दवा उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।

आज विश्व के कई देशों में विश्व सत्ता की योजना अपने तीसरे चरण से गुजर रही है।

वर्ष 2030 तक विश्व सत्ता अपना तीसरा चरण पूरा करने के उपरांत चौथे चरण में प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद पूरी दुनिया बदल जायेगी।

न तो कोई देश होगा, न ही कोई संविधान होगा और न ही किसी देश की कोई सत्ता होगी।

पूरी दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही कानून होगा, एक ही मुद्रा होगी और एक ही सत्ता होगी।

जिस को नियंत्रित करने के लिये पूरे विश्व की एक ही सरकार होगी। जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से विश्व के हर कोने में अपने हर नागरिक को नियंत्रित करेगी। जो नियंत्रण में नहीं आयेगा उसे ख़त्म कर दिया जायेगा। यही है इस पृथ्वी पर मनुष्य का भविष्य।

साप्ताहिक समय माया

आम खाद्य पदार्थों में जोड़े जाने वाले 7 सबसे हानिकारक रसायन

अपने भोजन को अपनी औषधि बनने दो। खैर, ज्ञान की ये बातें सच हो सकती हैं, लेकिन जब हम अपने आस-पास प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को देखते हैं, तो यह मुश्किल लगता है कि भोजन को औषधि बना दिया जाए। रसायनों और खाद्य योजकों का उपयोग कई खाद्य पदार्थों को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है, और ऐसे खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन घातक भी हो सकता है। इन 7 सामान्य खाद्य रसायनों के बारे में जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें जो खाद्य पदार्थों में जोड़े जाते हैं और मानव शरीर के लिए स्वस्थ नहीं हैं।

मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी)

यह स्वादिष्ट व्यंजनों में मिलाया जाने वाला एक आम खाद्य पदार्थ है। इस एडिटिव का मानव मस्तिष्क स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी जुड़ा है।

कृत्रिम खाद्य रंग

शोध से पता चलता है कि कृत्रिम खाद्य रंग संवेदनशील बच्चों में अतिसक्रियता पैदा कर सकता है और एलर्जी का कारण बन सकता है। लाल रंग के इस्तेमाल से थायराइड ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है।

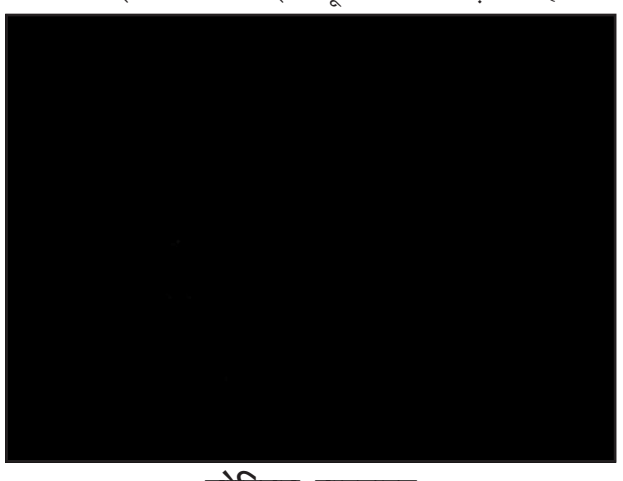

सोडियम नाइट्राइट

यह प्रसंस्कृत मांस में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य रसायन है जिसे नाइट्रोसामाइन नामक हानिकारक यौगिक में परिवर्तित किया जा सकता है। इस रसायन के नियमित सेवन से कई प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।

हाई-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप

आमतौर पर सोडा, जूस, कैंडी, नाश्ते के अनाज और स्नैक्स में इस्तेमाल किया जाने वाला यह रसायन वजन बढ़ने, मधुमेह और सूजन से जुड़ा हुआ है।

कृत्रिम मिठास

सबसे आम प्रकार के कृत्रिम मिठास एस्पार्टेम, सुक्रालोज़, सैकरीन और एसेसल्फेम पोटेशियम हैं। हालांकि वे वजन घटाने और रक्त शर्करा नियंत्रण को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप सिरदर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

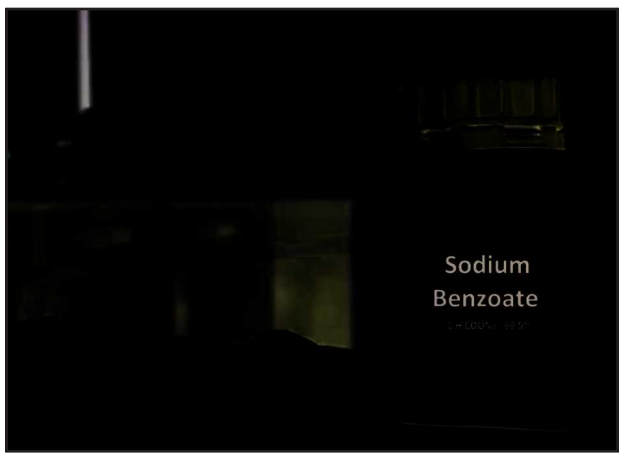

सोडियम बेंजोएट

भले ही इस रसायन को एफडीए द्वारा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ऐसे अध्ययन हैं जो सुझाव देते हैं कि यह मनुष्यों के लिए संभावित रूप से हानिकारक है। इसे बढ़ी हुई सक्रियता के साथ जोड़ा गया है और जब विटामिन सी के साथ मिलाया जाता है, तो यह कैंसर के विकास से जुड़ा हो सकता है।

ट्रांस वसा

यह एक प्रकार का असंतृप्त वसा है जिसका हाइड्रोजनीकरण हुआ है, जो शेल्फ जीवन को बढ़ाता है और उत्पादों की स्थिरता में सुधार करता है। यह आमतौर पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हृदय रोग के उच्च जोखिम से जुड़ा होता है। यह सूजन और मधुमेह का कारण भी बनता है।

ज्यादातर एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ हैं जो हम रोजाना खाते हैं

ये सामान्य खाद्य पदार्थ गुप्त खाद्य एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं

हम अक्सर एलर्जी के लिए उन खाद्य पदार्थों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो हम बाहर खाते हैं, लेकिन आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि घर का बना खाना भी खाद्य एलर्जी का कारण बन सकता है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भोजन जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो न केवल अचानक एलर्जी पैदा करके सिस्टम पर कहर बरपा सकते हैं, बल्कि अंतर्निहित खाद्य एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए घातक भी हो सकते हैं।

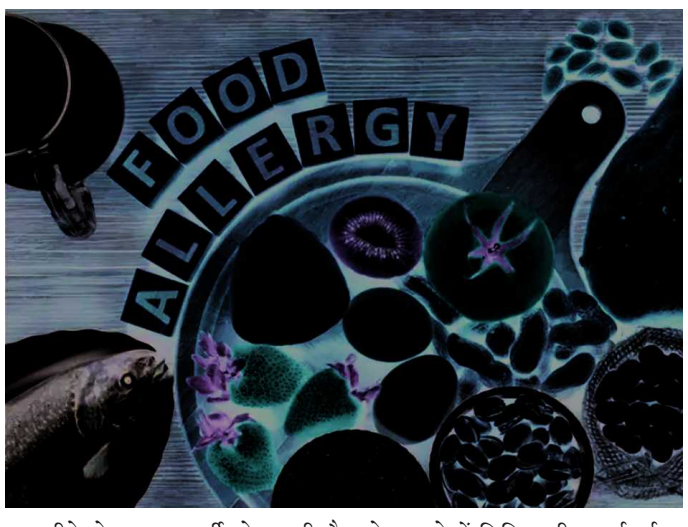

गाय का दूध

क्या आपको कभी दूध पीने के बाद अजीब सी बेचैनी और परेशानी महसूस हुई है? खैर, हम अक्सर इसके लिए लैक्टोज असहिष्णुता नामक एक सामान्य स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। डेयरी आधारित दूध पीने से खाद्य एलर्जी हो सकती है और यह शिशुओं और 3 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत आम है।

हालाँकि अधिकांश अध्ययनों का दावा है कि बच्चे कुछ वर्षों के बाद इस स्थिति से उबर जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया कि गाय या डेयरी आधारित दूध पीने से ये स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं जो खाद्य एलर्जी का संकेत देती हैं:

सूजन, चकत्ते, पित्ती, उल्टी, और, दुर्लभ मामलों में, एनाफिलेक्सिस। दूध से खाद्य एलर्जी के मामले में प्रतिक्रिया सेवन के 5-6 मिनट बाद तुरंत शुरू हो जाती है, लेकिन गैर-एलर्जी प्रतिक्रियाओं के मामले में यह पाचन स्वास्थ्य और आंत स्वास्थ्य को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है।

अंडे

अंडे सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक हैं और इनसे होने वाली एलर्जी बहुत आम हो सकती है। डिजिटल जर्नल, द हेल्थलाइन के अनुसार, लगभग 68% बच्चों को अंडों से एलर्जी है और अक्सर 16 साल की उम्र तक उनकी एलर्जी खत्म हो जाती है। इस एलर्जी के लक्षण सूक्ष्म से लेकर घातक तक रह सकते हैं, जो दुर्लभ है। कुछ सामान्य लक्षणों में पेट दर्द, दस्त, त्वचा पर चकत्ते, श्वसन संबंधी समस्याएं और एनाफिलेक्सिस शामिल हो सकते हैं। अंडे से होने वाली एलर्जी अंडे की सफेदी से लेकर अंडे की जर्दी तक भिन्न हो सकती है। इसलिए, अंडे खाने के बाद अचानक होने वाली प्रतिक्रियाओं के मामले में चिकित्सकीय मार्गदर्शन अवश्य लें।

मूँगफली

एक और सबसे आम और घातक एलर्जी मूंगफली एलर्जी है, जो बच्चों और वयस्कों दोनों में आम है। मूंगफली एलर्जी के लक्षण त्वचा पर चकत्ते से लेकर पुरानी लालिमा, खुजली या मुंह और गले के आसपास झुनझुनी तक हो सकते हैं, जिससे मतली या उल्टी हो सकती है या गला फंसने जैसा महसूस हो सकता है। यह एलर्जी मूंगफली के मक्खन के सेवन और जीवन भर इस अखरोट से परहेज करने के कारण भी हो सकती है।

GIUTEN
FREE
स्नेक्स
लंच

वर्षों से जमे भ्रष्ट अधिकारियो का कब करेंगे स्थानांतरण

कृषि को कृषि विभाग का भ्रष्टाचार कर रहा बर्बाद

वर्षों से 15 जिलों के संयुक्त संचालक के पद पर जमें आलोक मीणा का कब होगा स्थानांतरण

पूरे विश्व के देशों की सरकारें मानव जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता भोजन के लिए कृषि पर निर्भर करती हैं और उसकी मजबूती के लिए उसे हर प्रकार सेअनुदान सहयोग तकनीकी जानकारियां देकर वहां के कृषकों को मजबूत रखती हैं ताकि वे कृषि कार्य कर अपने देश की जनता के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकें। इसके विपरीतन केवल देश का और दुनिया के अनेकों देश का किसानकृषि कार्य करते हुए कृषि में जन्म लेता है जीता है और कर्ज में ही मर जाता है का यह ब्रह्म वाक्य पूरी दुनिया पर लागू होता है? क्योंकि सरकारों में बैठे कृषि मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी पूंजीपति व्यापारी उसका हर तरह से भरपूर शोषण करते हैं। तो हमारा प्रदेश और उसके हर जिलों में स्थित कार्यालयों में वर्षों से भ्रष्टाचार के दम पर बैठे कृषि विस्तार अधिकारी से लेकर उप संचालक, संयुक्त संचालक तक सरकारी योजनाओं कार्यों में विभिन्न माध्यमों से भ्रष्टाचार कर शोषण करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। फिर जहां तक इंदौर का सवाल है तो इस व्यावसायिक नगरी में कृषि के लिए बीज खाद कीटनाशक कृषि उपकरण आदि के बड़े-बड़े

उत्पादक व विक्रेता कंपनियों के करले भी इंदौर नगर में है जो पूरे प्रदेश की कृषि को न केवल प्रभावित करते हैं। बल्कि कृषि फसलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ नई सरकार के नये मुख्यमंत्री मोहन यादव कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना भी बेचारे मंत्री मुख्यमंत्री बने हैं और कृषि सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय व हर कदम कमाई का स्रोत भी है। फिर घोर भ्रष्ट एस.एन. मिश्रा जो कृषि उत्पादन आयुक्त व अपर मुख्य सचिव के रूप में अशोक वर्णवाल अपने ऐतिहासिक भ्रष्टाचार, लूट और डकैती के लिए जाने जाते हैं। अब इसका प्रधान सचिव भी बन चुका है। तो स्वाभाविक है कि यह सभी अपनी मोटी कमाई के लिए जो जितने बड़े भ्रष्ट होंगे उनको उतना संरक्षण देकर पालकर मोटी कमाई की जाएगी और इस श्रृंखला में आलोक मीना जहां भी सहायक संचालक व उपसंचालक रहा अपने वसूली और माल की आपूर्ति गिरोहों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का भरपूर फायदा उठाकर मोटी कमाई करता रहा। और अभी भी इंदौर-उज्जैन के दोनों संभागों का संयुक्त संचालक बनकर प्रदेश के 15 कृषि के महत्वपूर्ण जिलों में प्रभार संभाल 15 जिले के उपसंचालकों से सरकारी योजनाओं में अपने मित्रों के व्यक्तिगत काम करने का दवाब डलवा कर कार्य करवाने का आदी है। कृषि विभाग में संयुक्त संचालक स्तर परबड़े-बड़े बीज खाद बीज कीटनाशक आदि की फैक्ट्री उत्पादकों देख-रेख नियंत्रण आदि सभी मोटी कमाई की जाती है। वही धन वह यहां जमा रहने में उपयोग करता है। बेशक इस हरामखोर का काला चिट्ठा छापने पर मुझे धमकाया था। बेशक यहां बैठा उपसंचालक एसएस राजपूत भी मोटा धन देकर उसके सहयोग में वहां वर्षों से कुंडली बारे बैठे जाट पाठक के साथ उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर आदि में भी ऐसे ही अनेकों सहायक संचालक जो मोटा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कुंडली मारे धन देकर जमे हैं। इन पर कोई भी चुनावी आचार संहिता विधानसभा या लोकसभा की नहीं लगती हैइन पर कभी कोई आंच नहीं आती और यह डटे हुए हैं।

तो स्वाभाविक है। सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर जबकि सारा कार्य कंप्यूटर पर हो रहा है साइट पर 25 बिंदुओं की जानकारियां उपलब्ध नहीं होती हैं और सीडी में देने की अपेक्षा डराने-धमकाने ज्यादा पैसा जमा करवाने के लिए हमेशा हजारों रुपए के फोटो कॉपी की पत्र भेजे जाते हैं तो आखिर कब तक अब तो सरकार बदल गई है इन सबको भी बदल जाना चाहिए।

मेरे सच को परखने के लिए सभी पदस्थ अधिकारियों की मात्र पिछले 6 महीनों की कॉल डिटेल निकालकर इनके भ्रष्टाचार का सच जाना जा सकता है।

राहुल गांधी ने कहा था पेटीएम पे टू मोदी : सत्य सामने

पेज 8 का शेष

जबकि चीन की एंट ग्रुप कंपनी की सहयोगी कंपनी एंटफिन के पास 13.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई का आदेश

रिजर्व बैंक ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 1 मार्च से खातों, वॉलेट और अन्य उपकरणों में नई जमा या टॉप-अप लेना बंद करने का आदेश दिया। मौजूदा ग्राहकों को अभी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड वापस मिल सकता है। आरबीआई ने कहा, '29 फरवरी, 2024 के बाद बैंक द्वारा फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं की जानी चाहिए।' जोड़ा गया.

पीएम मोदी सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में अराजकता ला दीः जयराम रमेश

कांग्रेस सांसद रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के तहत पिछले 10 वर्षों में बैंकिंग प्रणाली में केवल अराजकता आई है। 'पहला,

विनाशकारी नोटबंदी का फैसला, जो बिना किसी योजना के और आरबीआई की आपत्तियों के बिना लिया गया। फिर, 2018 में र्छ्इए के दिवालिया होने से NBFC सेक्टर पर असर पड़ा। 2018 में भी यस बैंक और डीएचएफएल में हजारों करोड़ के घोटाले हुए थे. लक्ष्मी विलास बैंक और पीएमसी बैंक भी फेल हुए. नीरव मोदी जैसे लोगों को जनता का पैसा लेकर भागने का मुफ्त वीजा मिल गया। यह आम भारतीय हैं जिन्हें अपनी बचत निकालने में असमर्थ छोड़ दिया गया है, 'उन्होंने कहा।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई क्यों?

2022 में, आरबीआई ने गैर-अनुपालन मुद्दों के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक जोड़ने को रोकने का निर्देश दिया। ऑडिट के बाद, लगातार गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं की पहचान की गई।

जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत आरबीआई ने अब बैंक को लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा समयसीमा निर्दिष्ट किए बिना नई जमा स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया है।

पेटीएम ने क्या कहा?

पेटीएम ने कहा कि वह आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तुरंत कदम उठाएगी। आदेश के कारण, उसे ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले अपनी वार्षिक आय पर रु. 300 से 500 करोड़ का सबसे खराब प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

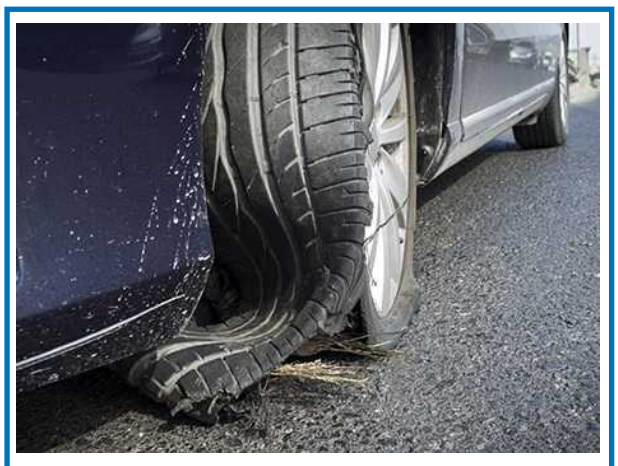

कार दुर्घटनाओं में पहियों की हवा का प्रेशर भी अहम

कल एक सड़क दुर्घटना में औरंगाबाद के सात युवकों की मौत हो गई.

एकमात्र कारण कार का टायर फटना था।

एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि नवनिर्मित एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में वाहनों के टायर फटने की घटनाएं देखी जा रही हैं। जिसमें हर दिन कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

ये आरडी कंक्रीट आरडी हैं जो टायरों के तापमान में अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं।

मेरे मन में सवाल आया कि देश की सबसे आधुनिक सड़कों पर ही सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? और दुर्घटना का केवल एक ही तरीका है और वह भी केवल टायर फटने से। बिल्डरों ने सड़क पर ऐसी कौन सी कीलें लगा दी हैं कि सबके टायर फट जाएं?

मेरे मन में तूफ़ान उठ गया, मैंने सोचा कि आज इस बात का पता लगा ही लूँ।

इसलिए हम कुछ शोध करने के लिए एकत्र हुए, हमने एक मित्र को परीक्षण के लिए स्कॉर्पियो एसयूवी लेने के लिए आमंत्रित किया और हम गए (ध्यान दें कि वास्तविक समस्या फ्लैट टायर है) सबसे पहले हमने ठंडे टायर के दबाव की जांच की और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार समायोजित किया जो कि है 25 साई

(सभी विकसित देशों की कारों में वायुदाब एक समान रखा जाता है

जब हमारे देश में लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर वे ईंधन बचाने के लिए टायरों में जरूरत से ज्यादा हवा भरवाते हैं जो आमतौर पर 35 से 45 पीएसआई होती है।

चलिए अब आगे बढ़ते हैं

इसके बाद हम फोरलेन पर चढ़े और कार चलाई, कार की स्पीड 120 - 140 किमी/घंटा रखी गई।

दो घंटे तक इतनी तेज गति से गाड़ी चलाने के बाद हम उदयपुर के पास पहुंच गए

हमने रुककर दोबारा टायर का प्रेशर चेक किया तो चौंक गए।

अब टायर का दबाव 52 पीएसआई था

अब सवाल ये उठता है कि टायर का प्रेशर इतना कैसे बढ़ गया

इसलिए जब टायर पर थर्मामीटर लगाया गया तो टायर का तापमान 92.5 डिग्री सेल्सियस था।

अब पूरा रहस्य खुल गया है कि सड़क पर टायरों के घर्षण और ब्रेक से पैदा होने वाली गर्मी के कारण टायरों के अंदर की हवा फैलती है।

टायरों में हवा का दबाव बहुत अधिक है

यदि हमारे टायरों में हवा पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, तो वे फटने से बच जाते हैं।

लेकिन जो टायर पहले से ही फुलाए हुए हैं (35 -45 पीएसआई) या जो टायर कट गया है, उसके फटने की संभावना अधिक होती है।

इसलिए चार लेन पर जाने से पहले अपने टायर का दबाव ठीक कर लें और सुरक्षित सवारी का आनंद लें

मैं एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से अनुरोध करता हूं कि वह ड्राइवरों को इस बारे में जागरूक करें ताकि हाईवे पर यात्रा किसी की आखिरी यात्रा न बन जाए।

सलाह... टायर में हवा की जगह नाइट्रोजन गैस भरें!! इसमें विस्तार का गुणांक कम है। यह कार्य बलपूर्वक किया जाना चाहिए। इससे टायर का तापमान बढ़ने पर अंदर की गैस ज्यादा नहीं फैलेगी और घर्षण के कारण उसका तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा.!!

(अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों से अनुरोध है कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें।)

यदि आप ऐसा करके किसी की जान भी बचा लें तो भी आपका मनुष्य जन्म धन्य हो जायेगा।

यह महत्वपूर्ण संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए।

मोदी की गारंटी वाला अंतरिम बजट महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं को क्या मिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 का एलान कर दिया है। यह बजट अंतरिम था और इससे बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन चुनावी साल को देखते हुए साल ने अंतरिम बजट में भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए कई बड़े एलान किए हैं। आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में विभिन्न वर्गों को क्या दिया है।

बजट की खास बातें...

- **टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं:** वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले की तरह आयकर सीमा 7 लाख बनी रहेगी, जिससे नौकरीपेशा को कोई फायदा नहीं होगा।
- **फ्री बिजली का एलान:** वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एलान करते हुए कहा कि आने वाले समय में रूफटॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत होने की उम्मीद है।
- **हाउसिंग स्कीम लाएगी सरकार:** वित्त मंत्री ने हर गरीब को घर देने का एलान किया है। सीतारमण ने कहा कि किराए के मकानों, झुग्गियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने के लिए सरकार नई हाउसिंग स्कीम लाएगी।
- **4 करोड़ मकानों का लक्ष्य होगा पूरा:** वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार हर गरीब को घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार 2 करोड़ घर गरीबों को सौंप चुकी है और 4 करोड़ घरों का लक्ष्य प्राप्त करने के नजदीक है। सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 फीसद महिलाओं को घर देने का काम किया है।
- **मेडिकल कॉलेजों का होगा विस्तार:** सीतारमण ने कहा कि सरकार मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
- **सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण अभियान:** सरकार सर्वाइकल कैंसर का खात्मा करने के लिए 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित देगी।
- **आयुष्मान भारत का विस्तार:** सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर का विस्तार हुआ है।
- **रक्षा खर्च बढ़ा:** वित्त मंत्री ने कहा सरकार ने रक्षा खर्च को 11.1 फीसद तक बढ़ाया है, यह GDP का 3.4 फीसद होगा।
- **रेल होगी अपग्रेड:** वंदेभारत स्तर के 40 हजार रेल डिब्बे बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए 3 अलग कॉरिडोर बनाएं जाएंगे।
- **महिलाएं बनीं लखपति:** वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई है और अभी तक एक करोड़ को लखपति बना दिया है।

टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी एक करोड़ करदाताओं को फायदा

वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वर्ष 1962 जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं। वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। कर दरो, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब सिर्फ 10 दिन में रिफंड मिल रहा है।

मध्यम वर्ग के लिए हुए ये एलान

सरकार 'किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले' मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी।

पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना इस योजना के तहत सरकार ने तीन करोड़ आवास बनाने का एलान किया है। इनमें से दो करोड़ आवास अगले पांच वर्षों में बनाए जाएंगे। इस तरह सरकार ने देश की ग्रामीण जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये की गई है।

सरकार ने बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का एलान किया है। इसके तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। साथ ही ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।

नारी शक्ति पर फोकस

महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।

30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28 प्रतिशत का उछाल आया है।

सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराएगी।

मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।

मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के लिए U-WIN प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधी जानकारी ली जा सकेगी।

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।

रेल परियोजनाओं के लिए मध्यप्रदेश को 15 हजार करोड़ का बजट आवंटन

मध्य प्रदेश में रेलवे की विकास परियोजनाओं के लिए साल 2024-2025 में 15 हजार करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया. इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है. अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है. रेलवे ने आधुनिकरण और यात्री सुविधाओं में बिस्तर पर विशेष फोकस किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरवार (1 फरवरी) को संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया. इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए रणनीति में बदलाव कर अधिकाधिक निवेश पर बल दिया गया है. इससे रेलवे की क्षमता वृद्धि, आधुनिकीकरण, संरक्षा और यात्री सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया है.

रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपये का बजट

उन्होंने बताया कि साल 2024-25 में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि रेलवे में तीन बड़े कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. इसमें एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा. इन कॉरिडोर के बनने से देश में आर्थिक विकास का बल मिलेगा. इसके साथ ही 40 हजार कोच को वंदे भारत के मानक के अनुरूप तैयार किया जाएगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश के बारे में रेलवे के बजटीय प्रावधान की जानकारी दी. उन्होंने बताया 'मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा प्रदेश है. साल 2009-14 तक मध्य प्रदेश को औसत बजट मात्र 632 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलता था, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 के बजट में बढ़ाकर 15 हजार 143 करोड़ रुपये किया गया है. यह अभी तक का मध्य प्रदेश के लिए सर्वाधिक बजट आवंटन है. रेल मंत्री ने बताया मध्य प्रदेश में रेल कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं.'

एमपी में 100 फीसदी रेल लाइनों का विद्युतीकरण

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रदेश में 77 हजार करोड़ रुपये के निवेश से बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में 100 फीसदी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो गया है. 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 972 फ्लाईओवर और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढावा देने के लिए एक स्टेशन-एक उत्पाद की 69 स्टॉल संचालित हो रहे हैं. रेल मंत्री ने बताया कि स्टेशनों पर बहुत अधिक फुटफॉल रहता है, जिससे स्थानीय उत्पादों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और स्टॉल संचालकों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है.अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात भी कही. रेल मंत्री के रेलवे बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय भी मुख्यालय सभागार में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल जुड़ी थीं.

साप्ताहिक समय माया

पाखंडी आरएसएस व भाजपा द्वारा धर्म को धंधा बना

धर्म: सत्ता द्वारा सनातनियों को भ्रमित व शोषण के हथियार

तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल बना मनोरंजन व व्यभिचार के अड्डे कर रहे विकसित

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजनीतिक मुखोटे भाजपा द्वारा देश के संविधान और उसके नियमों को ताक पर रख जिस प्रकारसे से सनातनियों के तीर्थ क्षेत्रों काशी, ओंकारेश्वर, उज्जैन, अयोध्या के प्राचीन स्वरूप वह उसके चारों तरफ बने छोटे ऐतिहासिक हजारों वर्ष पुराने हजारों मंदिरों, मढ़ियों, समाधियों को नष्ट कर जनधन के करों में वसूले शासकीय राजस्व व संयुक्त व्यावसायिक संगठनों से वसुले मोटे चंदे जिसे मोदी गिरोह चुपचाप हजम कर गया और बदले में वस्तुओं किचन ते जड़ से दोगुनी कर दी गई जिसका सीधा प्रभाव सीधे विद्यार्थियों कीपुस्तकों से लेकर मोटरसाइकिल कारों मोबाइलों वस्त्रों दैनिक उपयोग की भोजन सामग्री अनाज दुल्हन तिलहन तेल फल फ्रूट व अन्य सामग्री पर भी पड़ा।

दूसरी तरफ इन संगठनों के सनातनी नेताओं द्वारा जनता को धर्म की अफीम के नशा पिला उन्माद जो हूण शक मुगलडच पुर्तगीज अंग्रेजों के कारण शताब्दियों से सुप्त पड़ा था को अपनी धर्म संस्कृति परंपराएंकी दुहाई की वाचालता से जागृत कर, उनका शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक शोषण कर छल बल दल से पहले सत्ता हथियाई। सत्ता के हाथ में आते ही उनके ही प्राचीन पावन तीर्थ क्षेत्रों को मानसिक आध्यात्मिक शांति केंद्रों की आधारभूत विशेषता को नष्ट कर पर्यटन स्थल में बदल मनोरंजन केंद्र बना दिया और अभी के बजट में भीआप देखिए अध्यात्म से पर्यटन पर केंद्रित कर वार्षिक 30% तक आय वृद्धि की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सनातनियों को लूटने का षड़यंत्र किया जा रहा है।

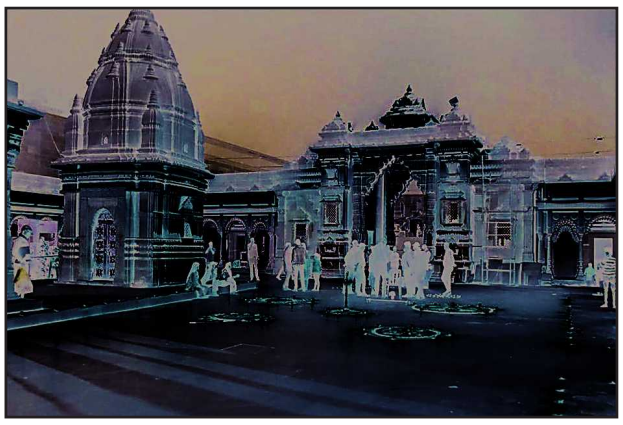

अध्यात्म से पर्यटन पर केंद्रित, सालाना 30% तक वृद्धि संभव

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में लगभग एक करोड़ विदेशी पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में देश में करीब 60 लाख विदेशी पर्यटक आए। इस बीच लक्षद्वीप से जुड़े सरकार के ऐलान को मालदीव के साथ हुए ताजा विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्योंकि इसके बाद देश से मालदीव जाने वाले लोगों ने लक्षद्वीप को लेकर खोज तेज की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा के बाद दुनिया भर में चर्चा में आया लक्षद्वीप अब देश के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। बजट में गुरुवार को सरकार ने इसके विकास के लिए नई परियोजनाओं को शुरु करने का ऐलान किया गया है। जिसमें पूरे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटकों से जुड़ी सुख-सुविधाओं का विकास शामिल है। सरकार का मानना है इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि देश के सबसे छोटे केंद्रशासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजूबती मिलेगी।

लक्षद्वीप सहित सभी द्वीप समूहों के लिए नई परियोजनाओं का एलान

समुद्र से घिरे लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी है। जहां छोटे-छोटे कई द्वीप समूह है, जो पर्यटकों को खूब भाते है। पर्यटन विकास का रोजगार के साथ सीधे जुड़ाव को देखते हुए सरकार ने सभी प्रमुख पर्यटन केंद्रों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से भी लैस करने का फैसला लिया है। इनमें आध्यात्मिक तीर्थाटन भी शामिल है। जिसमें पिछले सालों में बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है।

आध्यात्मिक तीर्थाटन को बढ़ावा देने का एलान

काशी विश्वनाथ के बाद अयोध्या अब देश के एक बड़े आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में सामने आया है। जहां श्रीराम मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन तीन से चार लाख लोग पहुंच रहे है। इसके साथ ही सरकार ने सभी राज्यों के प्रमुख पर्यटन केंद्रों की न सिर्फ वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करने का फैसला लिया है बल्कि उनकी सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता की रेटिंग भी की जाएगी। इसके लिए जल्द ही फ्रेमवर्क तैयार करने का भी ऐलान किया है।

प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विकास व ब्रांडिंग का फैसला

राज्यों को अपने प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर सुविधाओं को जुटाने के लिए ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण भी दिया जाएगा। वैसे भी जी-20 की देश भर के प्रमुख स्थानों पर हुई बैठकों के बाद वहां घरेलू पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों का भी रुझान बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसका जिक्र भी किया और कहा कि जी- 20 के आयोजन के दौरान भारत ने अपनी विविधता और खूबसूरती को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, उससे वहां घरेलू पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों की भी आवाजाही बढ़ी है।

विदेशी पर्यटकों को लाने का लक्ष्य

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में लगभग एक करोड़ विदेशी पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में देश में करीब 60 लाख विदेशी पर्यटक आए है। इस बीच लक्षद्वीप से जुड़े सरकार के ऐलान को मालदीव के साथ हुए ताजा विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्योंकि इसके बाद देश से मालदीव जाने वाले लोगों ने लक्षद्वीप को लेकर खोज तेज की है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक हर साल औसतन दो लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटन के लिए मालदीव जाते थे जिनकी संख्या पिछले कुछ दिनों में तेजी से गिरी है।

राहुल गांधी ने कहा था पेटीएम पे टू मोदी : सत्य सामने

चीन की दोस्ती और जनता से लूट, पैसा मोदी व मित्रों को

आरबीआई के पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आदेश के बाद कांग्रेस का 'चीनी लिंक' मोदी सरकार पर कटाक्ष

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने से रोक दिया। कांग्रेस ने पेटीएम के चीनी लिंक की सरकार की निगरानी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नई जमा स्वीकार करना बंद करने के निर्देश का आम आदमी पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पार्टी ने इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की 'चीनी लिंक वाली कंपनी, जिसे पहले भी दंड का सामना करना पड़ा है' पर नजर रखने में विफलता को जिम्मेदार ठहराया।

एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा, 'चीनी लिंक वाली एक फर्म क्यों है - एक बिंदु पर 31 प्रतिशत चीनी स्वामित्व और रु. 7000 करोड़ से अधिक के चीनी निवेश के साथ - जिसे पहले दंडित किया गया है 2022 में गैर-अनुपालन के लिए आरबीआई को कड़ी निगरानी में नहीं रखा जाएगा?'

उन्होंने कहा, 'क्या इसका 9 नवंबर 2016 को विनाशकारी नोटबंदी के फैसले पर पेटीएम के मुखर समर्थन से कोई लेना-देना है?'

पेटीएम में चीन की हिस्सेदारी

फिनटेक दिग्गज पेटीएम के मालिक और संचालक, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के सबसे बड़े शेयरधारक विजय शेखर शर्मा के पास 19.42 प्रतिशत हिस्सेदारी है,

(शेष पेज 6 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958